India (RBI) the benefits of fertiliser and electricity subsidies are not reaching the small and medium farmers in the country;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps Government propose to take to help the small and medium farmers in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Two studies namely Agricultural Policy in India—Context, Issues and Instruments, and Farm Input Subsidies and State Finances (a case study of Maharashtra and Uttar Pradesh) were done by the Reserve Bank of India. However, both these studies are silent about the benefits of fertiliser and electricity subsidies to the small and medium farmers in the country.

(c) In order to provide some relief to the farmers including the small and medium, the Government have allocated Rs. 756 crores during 1993-94 to provide the decontrolled fertilisers at subsidised rates.

महिला कल्याण हेतु बजट आबंटन में कटौती

1895. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक की शर्तों के अंतर्गत महिलाओं की उपेक्षा की गई है जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट है कि महिलाओं से संबंधित योजनाओं संबंधी परिव्यय में कटौती की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो महिलाओं से संबंधित योजनाओं के परिव्यय में कटौती करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1993-94 के बजट आबंटन में "महिला कल्याण" मद के अंतर्गत 49.36 प्रतिशत कटौती की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) 1992-93 के लिए संशोधित अनुमानों में 112.33 करोड़ रु० के बजट आवंटन में 24.50 करोड़ रु० अतिरिक्त लाभभोगियों हेतु अनुपूरक पौष्टिकता की योजना के लिए शामिल हैं जो 1993-94 से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं । इसको छोड़कर संशोधित अनुमान 87.83 करोड़ रुपये है । इसमें राष्ट्रीय महिला कृण कोष के समूहों के लिए एक बार अंशदान दिये जाने के लिए 31 करोड़ रु० की व्यवस्था शामिल है। महिलाओं के कल्याण की अन्य योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान 56.83 करोड़ रु० है। इसके मुकाबले महिलाओं के कल्याण के लिए 1993-94 का बजट अनुमान 62.97 करोड़ रु० है।

उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेशित राशि

1896. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 207 रुपए राष्ट्रीय औसत की तुलना में औसत 200 रुपए की राशि का निवेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में निवेश की राशि को राष्ट्रीय औसत के बराबर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?